

UPPCS-RO/ARO-BEO

हल प्रश्न-पत्र

सामान्य अध्ययन

प्रश्नावलोकन (वस्तुनिष्ठ रूप में)

विगत वर्षों के प्रश्नों की अध्यायवार व्याख्या (विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक रूप में)
अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ

भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

- UPPCS प्रारंभिक परीक्षा (2002-23)
- UPPCS मुख्य परीक्षा (2003-17)
- UPPSC BEO प्रारंभिक परीक्षा (2006-2007, 2020)
- UPPSC RO/ARO प्रारंभिक परीक्षा (2010-21)
- UPPSC RO/ARO मुख्य परीक्षा (2010-21)

संपादक

एन. एन. ओझा

संकलन व हल

क्रॉनिकल संपादकीय समूह



CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था

संवैधानिक ढांचा

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....	3
2. संविधान का निर्माण और विशेषता.....	6
3. संविधान की प्रस्तावना.....	12
4. संविधान की मूल संरचना.....	16
5. भारतीय संविधान के स्रोत.....	17
6. संघ एवं राज्य क्षेत्र.....	18
7. नागरिकता.....	25
8. मौलिक अधिकार.....	26
9. राज्य के नीति निर्देशक तत्व.....	36
10. मूल कर्तव्य.....	40
11. संविधान संशोधन.....	44

सरकार की प्रणाली

12. संसदीय एवं संघीय व्यवस्था.....	49
13. केंद्र राज्य संबंध.....	52
14. आपात उपबंध.....	56
15. अंतरराज्यीय संबंध.....	58

केंद्र सरकार

16. राष्ट्रपति.....	61
17. उपराष्ट्रपति.....	67
18. प्रधानमंत्री.....	69
19. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्.....	71
20. संसद.....	74
21. लोक सभा.....	84
22. राज्य सभा.....	89
23. संसद की समितियां.....	92

राज्य सरकार

24. राज्यपाल.....	97
25. राज्य विधानमंडल.....	99

न्यायपालिका

26. सर्वोच्च न्यायालय.....	103
27. उच्च न्यायालय.....	109
28. भारतीय न्यायपालिका : विविध आयाम.....	110

स्थानीय स्वशासन

29. पंचायतीराज.....	112
30. शहरी स्वशासन.....	122

संवैधानिक निकाय

31. निर्वाचन आयोग.....	124
32. संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग.....	125
33. वित्त आयोग.....	126
34. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक.....	128
35. महान्यायवादी और महाधिवक्ता.....	130

गैर – संवैधानिक निकाय

36. नीति एवं योजना आयोग.....	133
37. मानवाधिकार आयोग.....	134
38. सतर्कता आयोग.....	135
39. लोकपाल एवं लोकायुक्त.....	135
40. अन्य आयोग.....	135

विविध

41. भारतीय संविधान के अनुच्छेद/भाग.....	137
42. निर्वाचन प्रणाली.....	146
43. राजभाषा.....	150
44. कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध.....	151
45. संविधान की अनुसूचियां.....	158
46. उत्तर प्रदेश विशेष (राजव्यवस्था).....	162

भारतीय अर्थव्यवस्था

1. अर्थव्यवस्था की आधारभूत संकल्पना.....	3-9
2. भारत में आर्थिक नियोजन.....	10-14
> पंचवर्षीय योजनाएं.....	12
3. लोक वित्त.....	15-23
4. भारतीय वित्तीय एवं मौद्रिक नीति.....	24-43
> भारतीय रिजर्व बैंक.....	32
> वित्तीय समावेशन.....	36
5. कृषि और संबद्ध क्षेत्र.....	44-60
> खाद्य सुरक्षा एवं वितरण प्रणाली.....	57
> कृषि संबंधी योजनाएं और नीति.....	59
6. उद्योग और अवसंरचना.....	61-76
> निवेश और विनिवेश.....	69
> सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग.....	70
> औद्योगिक वित्त.....	71
> औद्योगिक योजना/नीति.....	71
7. सेवा और विदेश व्यापार.....	77-86
> रुपये का अवमूल्यन/परिवर्तनीयता.....	83
8. सामाजिक-आर्थिक विकास.....	87-113
9. समसामयिकी.....	114-114

पुस्तक के संबंध में

प्रिय पाठक

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पुस्तक को इस स्वरूप में तैयार करने का मुख्य कारण वर्तमान परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का विस्तृत होता दायरा है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर शोध करने से यह ज्ञात होता है कि अब प्रश्न पूर्व की भांति हू-ब-हू पुनरावृत्ति (रिपीट) न होकर पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की विषय वस्तु से ही संबंधित होते हैं, इसलिए वर्तमान में सिर्फ पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रश्नों की परिवर्तित प्रकृति को जानकर उसे परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से समझना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रस्तुत पुस्तक उपरोक्त आवश्यकता को संबोधित करती है, क्योंकि इसका संकलन न सिर्फ पूछे गए प्रश्नों के आधार पर किया गया है, बल्कि इसमें उन सभी तथ्यों और जानकारियों को भी समाहित किया गया है, जिनसे भविष्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

पुस्तक में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा और UPPSC-RO/ARO मुख्य परीक्षा के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। पूछे गए प्रश्नों के शोध के दौरान हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि वर्तमान समय में प्रश्न, पूर्व में आयोजित की गई मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों या उनकी विषय वस्तुओं से भी काफी अधिक संख्या में पूछे जा रहे हैं। अतः संकलन में हमने मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी समाहित किया है।

पुस्तक में विगत वर्षों के प्रश्नों का त्रुटिरहित उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सभी उत्तर आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुरूप हैं।

पुस्तक में सही विकल्पों के अतिरिक्त अन्य विकल्पों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की गई है तथा इस अतिरिक्त पाठ्य सामग्री को **व्याख्या** के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अतिरिक्त पाठ्य सामग्री अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगी। इस पुस्तक में प्रश्नों के हल के पश्चात की गई व्याख्या का अध्ययन उस प्रश्न से संबंधित विषय या टॉपिक पर पाठ्य सामग्री की जरूरत को पूरा करता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति राज्य के अन्य आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं [प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET), प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि द्वारा आयोजित परीक्षाएं] में भी होती है। अतः यह संकलन परीक्षार्थियों के लिए भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के अभ्यास हेतु भी उपयोगी है।

उम्मीद है कि क्रॉनिकल प्रकाशन समूह की यह पुस्तक आप सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी तथा बाजार में उपलब्ध अन्य हल प्रश्न-पत्रों से अपनी अलग पहचान स्थापित करेगी।

संपादक

भारतीय राजव्यवस्था

संवैधानिक ढांचा

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रश्न: ब्रिटिश इण्डिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर 'विभाग' या 'विभागीय पद्धति' द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया?

- (a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
- (b) भारत सरकार अधिनियम, 1858
- (c) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- (d) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

उत्तर: (a), भारतीय परिषद अधिनियम-1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अधिनियम ने सरकार की शक्तियों और कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया। यह प्रथम अवसर था, जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग-अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की।

व्याख्या: वायसराय की परिषदों का विस्तार किया गया और कानून निर्माण के उद्देश्य से अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 तक कर दी गयी। ये सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित किये जाते थे और इनका कार्यकाल दो साल था।

❖ कैनिंग ने 1859 ई. में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग-अलग विभाग सौंपे गए। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ई. में तीन भारतीय सदस्यों को अपनी परिषद में शामिल किया; जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव शामिल थे।

प्रश्न: यह किसने कहा- "मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्साहित कर दिया गया है"?

- (a) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (b) सरदार पटेल
- (c) जवाहर लाल नेहरू
- (d) डॉ. बी. आर. अंबेडकर

[U.P.P.C.S (Mains) - 2015 Paper-II]

उत्तर: (c), 4 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉ. अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आलोचना का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है, मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता।

व्याख्या: डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्त की गई। इस समिति द्वारा तैयार प्रारूप समिति को 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया।

❖ डॉ. अंबेडकर के अनुसार किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी थी?

- (a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1831
- (b) भारतीय सरकार अधिनियम, 1909
- (c) भारतीय सरकार अधिनियम, 1919
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P.P.C.S. (Pre) 2014

उत्तर: (d), भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 1937 को की गई थी।

व्याख्या: यह भारत शासन अधिनियम, 1935 के आठ प्रमुख प्रावधानों (संघात्मक सरकार, केन्द्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन, द्विसदनीय केन्द्रीय विधायिका, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमण्डल, केन्द्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन तथा संघीय न्यायालय) में से एक है।

प्रश्न: भारत की संवैधानिक विकास भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था -

- (a) 26 जनवरी, 1950 को
- (b) 11 फरवरी, 1948 को
- (c) 26 नवम्बर, 1949 को
- (d) उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं

U.P.P.C.S. (Mains) - 2013 Paper-II

उत्तर: (c), भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 ई. को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया।

व्याख्या: इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे।

प्रश्न: एक 'संघीय व्यवस्था' और 'केन्द्र' में 'द्वैध शासन' भारत में लागू किया गया था

- (a) 1909 के अधिनियम द्वारा
- (b) 1919 के अधिनियम द्वारा
- (c) 1935 के अधिनियम द्वारा
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P.P.C.S. (Mains) - 2013 Paper-II

उत्तर: (c), 1935 भारत शासन अधिनियम की निम्न विशेषताएँ हैं- अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता; केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना; संघीय न्यायालय की व्यवस्था; ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत; साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार; वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया।

सरकार की प्रणाली

12. संसदीय एवं संघीय व्यवस्था

प्रश्न: सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गयी?

- (a) ग्रेट ब्रिटेन में (यू.के.) (b) बेल्जियम में
(c) फ्रांस में (d) स्विट्जरलैण्ड में

U.P.P.C.S. (Pre) 2018

उत्तर: (a), सर्वप्रथम संसदात्मक प्रकार की सरकार का गठन ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था।

व्याख्या: ब्रिटेन की संसदीय प्रकार की सरकार संवैधानिक राजतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली से परिचालित होती है। ब्रिटिश संसद को विश्व की संसदों की जननी कहा जाता है।

प्रश्न: भारत एक गणतंत्र है, जिसमें अन्तर्निहित है-

- (a) राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है
(b) देश स्वतंत्र है
(c) देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है
(d) देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 Paper-II

उत्तर: (a), भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है तथा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है।

व्याख्या: भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी, 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया तथा ब्रिटिश डोमिनियन से एक गणतंत्र तक भारत के परिवर्तन के रूप में मनाया।

प्रश्न: भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएं समान हैं?

1. अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हैं।
 2. अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं।
 3. राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है।
 4. उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं।
- (a) केवल 3 (b) केवल 3 तथा 4
(c) केवल 2, 3 तथा 4 (d) केवल 1, 3 तथा 4

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

उत्तर: (a), राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति का अधिकार दोनों देशों के बीच समान है।

व्याख्या: भारत एवं अमेरिका द्वारा गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं का चयन किया गया है, जिससे दोनों जगह राष्ट्रपति शासन का प्रमुख है। दोनों देशों के राष्ट्रपति को जेबी विटो अधिकार प्राप्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र में तो अमेरिका में राज्यों में निहित है। उच्च सदन में सदस्यों की नियुक्ति के मामले में अमेरिका में सभी सदस्य प्रत्येक राज्य से दो तथा भारत में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से एवं कुछ सदस्य (12 सदस्य) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?

- (a) संसदात्मक सरकार (b) अध्यक्षीय सरकार
(c) स्वतंत्र न्यायपालिका (d) संघात्मक सरकार

U.P.P.C.S. (Mains) - 2015 Paper-II

उत्तर: (b), भारतीय संविधान में अध्यक्षीय प्रणाली वाली सरकार की संकल्पना को शामिल नहीं किया गया है।

व्याख्या: भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की वजाए ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है।

- ❖ संसदीय प्रणाली को सरकार के बेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं, बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है।
- ❖ भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायालय की स्थापना करता है, जो अपने आपमें एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है।
- ❖ राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे- जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र, केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है।
- ❖ भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है।
- ❖ इसके दो अभिप्राय हैं- पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौता का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- ❖ **नोट:** संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

प्रश्न: निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है?

- (a) केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा
(b) पूर्ण रूप से लिखित संविधान
(c) एकहरी नागरिकता
(d) स्वतंत्र न्यायपालिका

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

उत्तर: (c), एकल नागरिकता भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण न होकर एकात्मक लक्षण है।

केंद्र सरकार

16. राष्ट्रपति

प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उप-राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था?

- (a) आर. वेंकटरमण (b) नीलम संजीवा रेड्डी
(c) डॉ. जाकिर हुसैन (d) डॉ. शंकर दयाल शर्मा

U.P.P.C.S. (Pre) - 2022

उत्तर: (b), नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व उप राष्ट्रपति के पद पर कभी नहीं रहे।

व्याख्या: वे भारत के पहले गैर काँग्रेसी राष्ट्रपति थे।

❖ नव-गठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष भी रहे हैं?

- (a) फखरुद्दीन अली अहमद
(b) डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(c) डॉ. जाकिर हुसैन
(d) नीलम संजीव रेड्डी

U.P.P.C.S. RO/ARO (Pre) - 2021

उत्तर: (d), फखरुद्दीन अली अहमद, डॉ. शंकरदयाल शर्मा एवं डॉ. जाकिर हुसैन में से नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से पहले लोक सभा अध्यक्ष भी रहे हैं।

व्याख्या: फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। 1938 में बारदोली के नेतृत्व उन्हें वित्तमंत्री भी बनाया गया। 1940 में सत्याग्रह आंदोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन की वजह से जेल गए।

❖ डॉ. शंकरदयाल शर्मा भारत के नवें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह भारत के आठवें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक सभ्य प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों में सम्मानित किया है।

❖ डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे तथा वह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 1963 में डॉ. जाकिर हुसैन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया।

❖ नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे।

प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के सन्दर्भ में निम्नांकित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. राष्ट्रपति, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।
2. राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है।

सही उत्तर का चयन, नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए।
कूट:

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 तथा 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

उत्तर: (c), संविधान के अनुच्छेद 87 में दिये गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत दो बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है- प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को।

व्याख्या: संसद के किसी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान संविधान में किया गया है। इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1919 में किया गया था और 1921 से यह चला आ रहा है। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं, वह सरकार ही तैयार करती है।

❖ इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में सरकार की आगे की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख किया जाता है।

प्रश्न: यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा?

- (a) प्रधानमंत्री
(b) लोकसभा अध्यक्ष
(c) भारत के प्रधान न्यायाधीश
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P.P.C.S. RO/ARO (Mains) - 2021

उत्तर: (c), यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके का निर्वहन करेगा।

प्रश्न: भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है?

- (a) अनुच्छेद 39 (b) अनुच्छेद 60
(c) अनुच्छेद 61 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 Paper-II

उत्तर: (c), भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रकिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है।

राज्य सरकार

24. राज्यपाल

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए:

1. राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है
2. वह विधानमण्डल का हिस्सा नहीं है
3. उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है
4. उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है

कूट:

- (a) 1 और 2 सही हैं (b) 1 और 3 सही हैं
(c) 2 और 4 सही हैं (d) सभी सही हैं

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

उत्तर: (b), अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है।

व्याख्या: अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्य विधानमण्डल राज्यपाल, विधान सभा तथा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों यथा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता एवं समाजसेवा में विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है।

❖ अनुच्छेद 168 राज्यपाल को राज्य विधि के सम्बन्ध में दण्ड के लघुकरण, परिहार एवं निलम्बन (मृत्यु दण्ड एवं केन्द्रीय विधि तथा अन्य राज्य विधि को छोड़कर) का अधिकार देता है।

प्रश्न: जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते होंगे

- (a) राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार
(b) राष्ट्रपति के निर्णयानुसार
(c) गृह मन्त्रालय के निर्णयानुसार
(d) इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें।

U.P.P.C.S. (Mains) - 2016 Paper-II

उत्तर: (d), अनु. 158 (3क) के अनुसार जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किए जाएंगे, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें।

व्याख्या: संविधान के अनु. 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा।

प्रश्न: निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?

- (a) राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है।
(b) कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता।
(c) एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए दो मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी।
(d) मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जाँचने के लिए न्यायालय अधिकृत है।

U.P.P.C.S. (Mains) - 2016 Paper-II

उत्तर: (d), संविधान के अनुच्छेद 163(3) में मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। शेष सभी कथन राज्यपाल/राष्ट्रपति के सन्दर्भ में सही हैं।

व्याख्या: अनु. 163(2) के तहत यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निश्चित अंतिम होगा। अनु. 163(3) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी।

प्रश्न: भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है?

- (a) राष्ट्रपति के
(b) राज्य के राज्यपाल के
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश के
(d) भारत के उपराष्ट्रपति के

U.P.P.C.S. (Mains) - 2009 Paper-II

उत्तर: (b), राज्य के राज्यपाल के प्रति महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

व्याख्या: महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनु. 61

❖ राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

❖ संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

न्यायपालिका

26. सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न: भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक “अभिलेख न्यायालय” है।

इसका आशय है कि-

- इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है।
- इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
- इसे अपनी अवमानना करने वालों को दण्डित करने की शक्ति है।
- इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

U.P.P.C.S. (Pre) 2008

उत्तर: (b), अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं-

व्याख्या: अनुच्छेद 124 (1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होगा तथा सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किये जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किये जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है।
- भारतीय संविधान में भाग पांच (संघ) एवं अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

प्रश्न: भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?

- केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा
- समस्त न्यायालयों द्वारा
- उपरोक्त में से कोई नहीं

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 Paper-II

उत्तर: (b), संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है।

व्याख्या: न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है।

- न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस, 1975) माना जाता है।
- अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) तथा अनुच्छेद 32 में इसकी व्यवस्था बताई गई है।

प्रश्न: नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): केंद्रीय कानूनों का सांविधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है।

कथन (R): सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

कूट:

- (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (A) तथा (R) दोनों सही हैं परन्तु (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (A) सही है किन्तु (R) गलत है।
- (A) गलत है, किन्तु (R) सही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2019

उत्तर: (a), सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों के संविधान से संगत या असंगत का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।

संविधान द्वारा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में अनन्य अधिकारिता का प्रयोग करता है। अतः कथन सही है।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में स्थापित किया गया है। यह किसी भी संवैधानिक संशोधन की संवैधानिकता जांच सकता है और उस विधि को निरस्त कर सकता है। अतः कारण सही है और कथन का स्पष्टीकरण है।

स्थानीय स्वशासन

29. पंचायतीराज

50. संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है-

1. पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए
2. महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए
3. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वित्त का अनिवार्य रूप से हस्तान्तरण
4. 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तान्तरण

नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

- (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

U.P.P.C.S. (Pre) - 2023

उत्तर: (d), भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान द्वारा संविधान के भाग-9 में 16 अनुच्छेद तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें पंचायती राजव्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर आरक्षण, राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायतों को वित्त का अनिवार्य रूप से हस्तान्तरण तथा 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों के शक्ति का हस्तान्तरण का प्रावधान है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन-सा सत्य नहीं है?

- (a) इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं।
- (b) इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है।
- (c) यह एक ग्राम स्तर की सभा है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं।
- (d) (a) तथा (c) दोनों

U.P.P.C.S. (Pre) - 2023

उत्तर: (b), ग्राम सभा को एक ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके समस्त मतदाताओं से मिलकर निर्मित होता है।

व्याख्या: ग्राम सभा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों की निगरानी करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत द्वारा गांव के विकास के लिए किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है।

❖ ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी निर्वाचित इकाई होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

❖ ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। वास्तव में, प्रत्येक राज्य में 'राज्य चुनाव आयोग' का गठन पंचायती राज चुनावों को संपन्न कराने के लिए ही किया गया है।

प्रश्न: पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन (1977) की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है/हैं?

1. पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्वि स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।
2. राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए।

नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन चुनिए-

कूट:

- (a) केवल 1 (b) 1 तथा 2 दोनों
(c) केवल 2 (d) न तो 1 न ही 2

U.P.P.C.S. (Pre) - 2023

उत्तर: (a), अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में तीन स्तर के संगठन के स्थान पर दो स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी।

अतः कथन 1 सत्य है जबकि दूसरा कथन असत्य है। राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें करीब 15000-20000 जनसंख्या एवं 10-15 गांव शामिल हों,

व्याख्या: दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए जनता सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी। इसने सिफारिश की थी की जिला स्तर पर जिला परिषद् और निम्न स्तर पर "मंडल पंचायत जिसे कई गांवों को मिलाकर बनाया जाना चाहिए।

अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की संस्तुति की। इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया- जिला में जिला परिषद्, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। इस समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया।

1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" का नाम दिया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था की आधारभूत संकल्पना

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी आर्थिक क्रिया नहीं है?

- (a) परिवहन (b) किसानी (खेती)
(c) नौकरी (d) स्वेच्छिक समाज सेवा

U.P.P.C.S. (Pre) - 2023

उत्तर: (d), स्वेच्छिक सामाजिक सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है।

व्याख्या: उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। उदाहरण- (क) एक व्यक्ति का अपने बाग में कार्य करना (ख) एक स्त्री द्वारा अपने पति के लिए खाना पकाना (ग) एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में सफेदी करना। सामाजिक जीवन में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। इनमें कुछ क्रियाएं मानसिक संतुष्टि या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। जो क्रियाएं धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है?

- (a) पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार
(b) जनसंख्या में परिवर्तन
(c) विशेषीकृत क्रियाओं/गतिविधियों में श्रम विभाजन
(d) तकनीकविद् एवं नौकरशाह

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

उत्तर: (d), आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है।

व्याख्या: आर्थिक विकास में गैर-आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है, जैसे- शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ, जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक विकास आदि।

❖ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, “विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है।” आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है।

प्रश्न: पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है?

- (a) उल्टा 'यू' आकार (b) उल्टा 'वी' आकार
(c) उल्टा 'एल' आकार (d) इनमें से कोई नहीं

U.P.P.C.S. (Pre) 2019

उत्तर: (a), कुजनेट्स वक्र की अवधारणा को उल्टा यू-आकार के वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

व्याख्या: अर्थशास्त्री कुजनेट्स द्वारा आर्थिक विकास एवं असमानता को स्पष्ट करने के लिए कुजनेट्स वक्र की अवधारणा रखी जिसके अनुसार आरम्भ में बाजार की ताकतों के कारण आर्थिक विकास के दौरान असमानता बढ़ती है, परन्तु एक निश्चित विकास स्तर की प्राप्ति के बाद विषमता स्तर में कमी आती है। इसी अवधारणा को पर्यावरण एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जिसके अनुसार आरम्भ में आर्थिक विकास के कारण पर्यावरणीय हास में वृद्धि होती है परन्तु एक निश्चित विकास स्तर की प्राप्ति के बाद इसमें गिरावट होती है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं?

1. कृषि मुख्य व्यवसाय
 2. प्रचलन बेरोजगारी
 3. मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता
 4. प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना
- नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

कूट:

- (a) केवल 1 तथा 2 (b) 1 तथा 4
(c) केवल 2 तथा 3 (d) 1, 2 तथा 3

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 - Paper-II

उत्तर: (d), इस अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषता होती है

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, “एक देश जिसकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय विकसित संयुक्त राज्य की प्रति व्यक्ति आय के एक चौथाई से कम है, एक विकासशील देश होगा।”

- ❖ सार्वभौमिक गरीबी।
- ❖ बढ़ती जनसंख्या को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने की क्षमता।
- ❖ पूंजी की कमी।
- ❖ अल्प-विकसित यातायात तथा संचार-व्यवस्था व अविकसित उद्योग।

प्रश्न: अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है:

1. प्रति व्यक्ति निम्न आय
 2. पूंजी निर्माण की निम्न दर
 3. निम्न आश्रितता अनुपात
 4. तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना
- नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

कूट:

- (a) 1 तथा 2 (b) 2 तथा 3
(c) 3 तथा 4 (d) 1 तथा 4

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 - Paper-II

उत्तर: (a), अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषता होती है-

भारत में आर्थिक नियोजन

प्रश्न: सूची-I को सूची-II के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर चयन कीजिए-

सूची-I (पंचवर्षीय योजना)	सूची-II (प्रयुक्त विकास मॉडल)
A. प्रथम	1. एस. चक्रवर्ती मॉडल
B. द्वितीय	2. हैरोड-डोमर मॉडल
C. तृतीय	3. अशोक रूद्र मॉडल
D. चतुर्थ	4. महालनोबिस मॉडल

कूट:	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	2	4	1	3
(c)	3	1	2	4
(d)	2	1	4	3

U.P.P.C.S. RO/ARO (Pre) - 2021

उत्तर: (b),

व्याख्या: पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगो के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है।

- ❖ इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करना है।
- ❖ प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951-56 में की गयी थी। जो कि हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। जिसका मुख्य उद्देश्य बांधों और सिंचाई में निवेश पर बल देना था।
- ❖ द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956-61 में की गयी थी। जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जिसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था।

प्रश्न: नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए।

1. सन्तुलित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए है।
2. विकास के लाभ को सम-आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए है।
3. क्षेत्रीय असन्तुलन के दूरीकरण को प्रमुखता देने के लिए है।
4. उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए है।

इनमें से

- (a) केवल 1 और 2 सही है
- (b) केवल 1, 2 और 3 सही है
- (c) केवल 2, 3 और 4 सही है
- (d) 1, 2, 3 और 4 सही है

U.P.P.C.S. (Mains) - 2016 Paper-II

उत्तर: (d), नियोजन का अर्थ पहले से यह निश्चय करना है कि भविष्य में क्या करना है तथा कैसे करना है। नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों

का निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि तथा सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा कार्यवाहियों को विकसित करने से है। नियोजन की आवश्यकता के सन्दर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

व्याख्या: नियोजन से तात्पर्य उद्देश्य के निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि विकसित करने से है।

प्रश्न: 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था

- (a) एन.आर. सरकार ने
- (b) कस्तूरी भाई लाल भाई ने
- (c) जयप्रकाश नारायण ने
- (d) श्रीमन नारायण अग्रवाल ने

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

उत्तर: (d), महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित होकर 1944 में वर्धा कामर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया गया था।

व्याख्या: गांधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ-साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था इसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया था।

प्रश्न: योजना आयोग का अन्त किस प्रधानमंत्री ने किया?

- (a) नरेन्द्र मोदी
- (b) मोरारजी देसाई
- (c) अटल बिहारी वाजपेयी
- (d) आई. के. गुजराल

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

उत्तर: (a), योजना आयोग की जगह 1 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के एक प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी थे।

व्याख्या: योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। यह भारत सरकार का चिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया?

- (a) ब्राजील ने
- (b) यू. एस. ए. ने
- (c) भारत ने
- (d) चीन ने

U.P.P.C.S. (Pre) - 2012

उत्तर: (c), परिवार नियोजन कार्यक्रम की विश्व में सर्वप्रथम शुरुआत भारत में हुई थी।

व्याख्या: वर्ष 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना था। यह कार्यक्रम प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ मातृ, शिशु एवं बाल मृत्यु दर तथा रोग दर को भी कम करता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 2016 से 7 उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा असम) में मिशन परिवार विकास चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 146 जिलों में गर्भनिरोधक तरीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

लोक वित्त

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था?

- (a) संयुक्त राज्य अमेरिका (b) फ्रांस
(c) भारत (d) जर्मनी

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 - Paper-II

उत्तर: (a), शून्य आधारित बजट की अवधारणा सबसे पहले पीटर फायर ने अमेरिका में दी थी।

व्याख्या: इस बजट के अन्तर्गत कोई पूर्व निर्धारित आधार नहीं होता है। अतः इस बजट के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती मदों को शून्य मान लिया जाता है। अर्थात् इस बजट का निर्माण बिना किसी आधार के किया जाता है। इस शब्द को “पीटर पायर” ने दिया था। सबसे पहले इस बजट को 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया था।

❖ शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय सम्बन्धी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है।

प्रश्न: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर-योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है:

- (a) वित्त आयोग (b) भारतीय रिजर्व बैंक
(c) वित्त मंत्रालय (d) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 - Paper-II

उत्तर: (a), केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर प्रदान किया जाता है।

व्याख्या: केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय व राजकोषीय संबंधों की व्याख्या संविधान के भाग-12 के अध्याय (1) में की गई है।

प्रश्न: खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं-

- (a) साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में
(b) साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में
(c) राजकोषीय नीति नियंत्रण में
(d) श्रम नीति नियंत्रण में

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 - Paper-II

उत्तर: (b), आइबीआई के परिणात्मक या मातात्मक साख नियंत्रण विधि में खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट शामिल है।

व्याख्या: खुला बाजार परिचालन (OMO) धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिये मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिये नियोजित की गई है। इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री, टिकाऊ चलनिधि डालना/अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल हैं। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिये खुले बाजार का संचालन किया जाता है।

प्रश्न: संघ-सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है?

- (a) प्रमुख आर्थिक साहाय्य (b) पेंशन
(c) वेतन तथा भत्ते (d) ब्याज अदायगी

U.P.P.C.S. (Mains) 2017 - Paper-II

उत्तर: (d), राजस्व व्यय केन्द्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदानों से परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकता है) आदि पर किये गए व्यय से होता है।

प्रश्न: लाभ मात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है-

- (a) बिक्री कीमत में वृद्धि
(b) बिक्री मिश्रण को बदलना
(c) परिवर्तनशील लागत को कम करना
(d) उपर्युक्त सभी

U.P.P.C.S. RO/ARO (Mains) - 2017

उत्तर (d), उपर्युक्त में से सभी विकल्प सत्य हैं।

व्याख्या: जब किसी इकाई का योगदान सीमा प्रतिशत के रूप में दिखायी जाती है, तब यह लाभ मात्रा अनुपात कहलाती है। यह अनुपात योगदान और विक्रय की कुल मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाता है। लाभ एवं विक्रय की मात्रा के बीच का अनुपात किसी भी व्यवसाय की लाभोत्पादकता का संकेतक होता है। इस अनुपात के आधार पर प्रबंधन सबसे अधिक लाभ का बिक्री क्षेत्र, उत्पादन की दिशा तथा विक्रय की विधि का चयन करती है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

- (a) नीति अनुमोदन प्रस्ताव - बजट की मांग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाए
(b) मितव्ययिता प्रस्ताव - बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए
(c) सांकेतिक प्रस्ताव - बजट की मांग में से एक सौ रुपए कम कर दिए जाएं
(d) लेखानुदान - बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना

U.P.P.C.S. (Pre) - 2017

उत्तर: (d), लेखानुदान सामान्यतः एक वर्ष की बजाए कुछ माह के लिए संसद से जरूरी खर्च के लिए अनुदान प्राप्त करना, के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें केवल खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें राजस्व का ब्यौरा नहीं होता है।

भारतीय वित्तीय एवं मौद्रिक नीति

प्रश्न: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?

- (a) कानपुर (b) लखनऊ
(c) गाजियाबाद (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
U.P.P.C.S. RO (Mains) - 2021

उत्तर: (b), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का मुख्यालय 'लखनऊ' में है।

व्याख्या: इसे 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास के लिए और साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई। यह संस्था एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है।

प्रश्न: निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें

कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-

- (1) नाबार्ड की स्थापना
(2) स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम
(3) किसान क्रेडिट कार्ड योजना
(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

कूट:

- (a) (4), (1), (2) और (3)
(b) (4), (2), (3) और (1)
(c) (1), (2), (3) और (4)
(d) (4), (3), (2) और (1)

U.P.P.C.S. RO (Mains) - 2021

उत्तर: (a), निम्न संस्थाओं का क्रम क्रमशः इस प्रकार है-

व्याख्या: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 1975 में 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

- ❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975
- ❖ नाबार्ड की स्थापना 1982
- ❖ स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93
- ❖ किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998

नाबार्ड की स्थापना 1982 - भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी)

के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 05 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित की गई।

- ❖ किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 - यह सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधित खर्च के लिए बैंक के माध्यम से बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है।
- ❖ स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में आरम्भ हुआ था।

प्रश्न: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गये एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है।

1. पैमाने की मितव्ययिता
2. पूँजी तक आसान पहुँच
3. व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार
4. विश्व स्तरीय आकार के बैंक

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही लाभों का चयन कीजिए:

कूट:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4 सभी
U.P.P.C.S. BEO (Pre) - 2020

उत्तर: (d), बैंकों के एकीकरण के लाभ-

- ❖ कंपनी की पहुँच का विस्तार करना।
- ❖ नए क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार करना।
- ❖ कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना।
- ❖ परिचालन लागत में भी कमी करना।
- ❖ बैंकों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि।

प्रश्न: निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए:

1. नाबार्ड की स्थापना
2. स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम
3. किसान क्रेडिट बैंक की स्थापना
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए।

कूट:

- (a) 4, 1, 2, 3 (b) 4, 2, 3, 1
(c) 1, 2, 3, 4 (d) 4, 3, 2, 1

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

उत्तर: (*), सही कालानुक्रम है-

व्याख्या: नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची I (क्रांति)		सूची II (संबंधित है)	
(A) गोल्डन क्रांति	1.	तिलहन उत्पादन	
(B) ग्रे क्रांति	2.	बागवानी एवं शहद	
(C) पीली क्रांति	3.	पेट्रोलियम उत्पादन	
(D) काली (ब्लैक) क्रांति	4.	उर्वरक	

कूट:	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	2	3	4	1
(c)	1	2	3	4
(d)	2	4	1	3

U.P.P.C.S. (Pre) - 2022

उत्तर: (d), काली क्रांति - पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।

- ❖ पीली क्रांति- तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
- ❖ ग्रे क्रांति- उर्वरक से संबंधित है।
- ❖ गोल्डन क्रांति- बागवानी और शहद उत्पादन से यह 1991 में आरंभ हुआ है।
- ❖ गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है।

प्रश्न: फसल चक्र के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- 1) गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलों उगानी चाहिए।
- 2) फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए-

कूट:	
(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों	(d) न तो 1 न ही 2

U.P.P.C.S. RO/ARO (Pre) - 2021

उत्तर: (b), किसी क्षेत्र से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगायी जाने वाली फसलों के क्रम को फसल चक्र कहते हैं।

व्याख्या: एक उत्तम फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं।

- 1) उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए।
- 2) अधिक खाद्य की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद्य की आवश्यकता वाली फसलों उगाना चाहिए।
- 3) अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों उगाना चाहिए।

- 4) फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को उगाना चाहिए।
- 5) कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से करना चाहिए। भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए।

प्रश्न: नाइजर (रामतिल) की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पायी जाती है?

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) 7 - 16% | (b) 17 - 26% |
| (c) 27 - 36% | (d) 37 - 47% |

U.P.P.C.S. RO/ARO (Pre) - 2021

उत्तर: (d), रामतिल के बीजों में 38-43 प्रतिशत तेल एवं 20 से 30 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा पायी जाती है। साथ ही इसके बीजों में 483 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 9 से 13% और कैल्शियम 180-800 की मात्रा पाई जाती है।

व्याख्या: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की जननी के नाम से जानी जाने वाली रामतिल एक तिलहनी फसल है। इस फसल को नमी के अभाव में अथवा विषम परिस्थितियों में अनुपजाऊ एवं कम उर्वराशक्ति वाली भूमि में भी उगाया जा सकता है। यह फसल भूमि का कटाव होने से रोकती है।

प्रश्न: सूची-I और सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (फल)	सूची-II (सबसे बड़ा उत्पादक)
(A) आम	(1) जम्मू और कश्मीर
(B) लीची	(2) केरल
(C) नारियल	(3) बिहार
(D) सेब	(4) उत्तर प्रदेश

कूट:	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	1	2	3	4
(c)	4	3	2	1
(d)	1	2	4	3

U.P.P.C.S. RO/ARO (Pre) - 2021

उत्तर: (c), विकल्प c सही उत्तर है।

व्याख्या: भारत में मुख्य आम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि देश के कुल आम उत्पादन का 23.86% हिस्सा है। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है।

❖ लीची के फल पोषक तत्वों से भरपूर एवं स्फूर्तिदायक होते हैं। इसके फल में शर्करा (11%), प्रोटीन (0.7%), वसा (0.3%), एवं अनेक विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार देश का सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य है।